River
25/06/2026

दिल जुड़ेंगे तभी तो जुड़ेंगी नदियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि नदियों को जोड़ने के रास्ते में बाधा बनने वाले जल विवादों का समाधान आपसी सहमति और सहयोग के जरिए निकाला जाए। 'प्रगति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने एक्स (X) पर पोस्ट में कहा कि 'प्रगति' सत्र के दौरान 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन नदियों को जोड़ने से शुरू किया और इसी से सम्बन्धित परियोजना पर फोकस किया।

इस सिलसिले में मोदी ने राज्यों से सहयोग, समय पर मंजूरी व प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के माध्यम से अंतरराज्यीय जल विवादों के हल की चर्चा के क्रम में केन-बेतवा नदियों को जोड़नेवाली परियोजना का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा परियोजना को आदर्श और मॉडल के रूप में देखे जाने की बात कही।

केन और बेतवा नदियों को जोड़नेवाली परियोजना पर काम के साथ-साथ विवाद भी चल रहे थे। प्रधानमंत्री के कथनानुसार इस मामले में आदर्श माना जा सकता है कि उनकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ (एनडीए) सरकार में नदियों को जोड़नेवाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में केन-बेतवा पहली परियोजना थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में केन-बेतवा परियोजना को मंजूरी दी थी और बताया गया कि इस पर 44,605 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वर्ष 2030 में इसका काम पूरा होना है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा नदी लिंक (जोड़) की आधारशिला रखी।

उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के 13 जिलों को केन-बेतवा नदियों से लाभान्वित करनेवाली इस परियोजना का उद्देश्य है सिंचाई जल-संकट से जूझते बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी पहुंचाना और पनबिजली पावर प्लांट स्थापित करना। उत्तरप्रदेश की मध्यप्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड आदिवासी क्षेत्र है, जिसकी पहचान ही स्थायी सूखाग्रस्त इलाके के रूप में होती है। दोनों राज्यों के बीच की नदी है, केन-बेतवा। केंद्र सरकार की ओर से परियोजना को यह कहकर मंजूर किया गया कि इससे केन नदी का अतिरिक्त पानी बुंदेलखंड की सूखी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इसमें केन नदी पर दौधन डैम और 221 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण भी शामिल है, जो केन से पानी बेतवा नदी तक पहुंचाएगी। (इसका स्वागत हुआ, बुंदेलखंड के लोग खुश हुए। मगर उनकी खुशी परियोजना की आधारशिला रखे जाने और काम शुरू होने के बाद ही दुख में बदल गयी। विवाद मुख्य रूप से यहां के मूल आदिवासी बाशिंदों की आजीविका और डैम, पनबिजली प्लांट निर्माण के लिए उन्हें जंगल से विस्थापित किए जाने के मुद्दे हैं। से सवाल से आंदोलनरत हैं विस्थापित होनेवालों को न तो उचित मुआवजा मिला है, न ही आदिवासियों की आजीविका के मुद्दे जल, वन, जमीन की बिजली-मुफ्ती बिजली दिए जाने का ठोस आश्वासन मिला है। इन्हीं मुद्दों, जिन्होंने मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के दौधन गांव में आंदोलन चला, जहां केन नदी पर डैम बनना है

आदिवासी (वनवासी – भाजपा के शब्दों में) किसानों के महिला-बच्चे समेत आंदोलन की शुरुआत 04 अप्रैल, 2026 से चिता आंदोलन से की। इसमें सैकड़ों किसान पत्नी, बहन, बेटियों – बच्चों के साथ बांस-बल्ली की चिताएं सजाकर लेट गए। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं धरना पर भी बैठी।

महिलाओं ने दोनों हाथों में लेकर माथे के ऊपर जो बैनर, तख्तियां रखी थी, उस पर लिखा था — [illegible] – न्याय से या मौत से।

आदिवासियों की आजीविका और सामाजिक संस्कृति का स्रोत प्राकृतिक संसाधनों के नाश से उनका असंतोष विभिन्न रूपों में लगातार सार्वजनिक सुर्खियों में आया। अनशन-आंदोलन के अंतर्गत उपवास रखा गया। मिट्टी आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों ने अपने शरीर को मिट्टी से ढंक दिया। जल-आंदोलन के अंतर्गत सब के सब कमर से नाक तक केन नदी में कई घंटे खड़े रहे। अप्रैल के फिर बाद और गर्दन भी के पानी में डुबोए रहे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मध्यप्रदेश प्रशासन के उनकी शिकायतें सुने जाने के आश्वासन पर आदिवासियों ने आंदोलन स्थगित किया। मई के अंतिम सप्ताह तक ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि राज्य सरकार ने केन-बेतवा परियोजना से पीड़ित वनवासियों को संतोषजनक कोई उपाय करने का भरोसा दिलाया हो। फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट हो इसकी अभी शुरुआत में ही इतनी उचित संगत हो

(4) क्योंकि मई के अंतिम सप्ताह में ही 51वीं प्रगति सत्र (1)

में प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा परियोजना को आदर्श रूप में रखके राज्यों से कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी से लागत बढ़ती है और नागरिकों को जरूरी सुविधाओं का लाभ भी समय पर नहीं मिल पाता। इस विलंब का लोगों के जीवन-स्तर पर असर पड़ता है। प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही और मौजूदा प्रसंग के अनुकूल है। इस विश्लेषण का तात्पर्य प्रधानमंत्री की पहल केन-बेतवा नदी-लिंक परियोजना को उनके सामर्थ्य सोच की सक्रिय उपेक्षा नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की। अब उसे समय से पूरा करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अधिकारियों से केन्द्र मंत्री तक जमीनी हकीकत का आकलन और साथ मूल्यांकन प्रभावित तथा लाभान्वित होनेवाले स्थानीय लोगों की शिकायतें दूर करने के बजाए सरकारी खानापूर्ती करके पल्ला झाड़ते रहते हैं।

नदियों को जोड़ने की योजना कोई नयी नहीं है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके लिए समिति बनवायी, जो के.एल. राव समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति ने देश भर की नदियों को जोड़ने की रूपरेखा 1970 में तय की। 1980 के दशक में इस योजना को तेजी से अमल में लाने के लिए एक एन.पी.पी. CNPP- नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान तैयार हुआ। इसके तहत 1982 में बनी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को देश की नदियों को जोड़ने का काम सौंपा और इसके लिए 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गयी।

इस योजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक पहली और इकमात्र परियोजना है जिसका कार्यान्वयन शुरू हुआ। इस परियोजना का काम दिया गया राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी — 2026

40 शेन्खाल में रेल-बेतवा लिंक के अमल में आने	(5)

के सबसे पहले में आनेवाली बुनियादी दिक्कतों की गहराई में गए

बगैर जल्दी-बाज़ी के कारण काम होता नहीं है।

इसका कारण है, इस जगह और आसपास के

जनजीवन की भावनाओं की उपेक्षा नदियों को जोड़ने के

क्रम में वहां के बाशिंदों के जुड़ाव को नजरअंदाज करने का

परिणाम है आंदोलन। केन नदी के तट दौधान गांव

में डैम बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण से 22 गांवों के

7,000 परिवार विस्थापित होंगे। उनमें से 10 गांव लगभग पूरी

तरह जलमग्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नदी-लिंक योजना

की मूल भावना ही विस्थापित और जलमग्न होने की भेंट चढ़

जाएगी। नदी-लिंक योजना का असली मकसद है

ऐसा जल-प्रबंधन, ताकि सब घाटी के अधजल होने की स्थिति

पैदा न हो और किसानों को हर मौसम में पानी मिले।

देश के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु और खेतों की जल-जरूरत

के हिसाब से भिन्न-भिन्न है। ~~पूर्वी भारत के बिहार, बंगाल, असम~~

पूर्वी भारत में हर साल बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होती है।

बाढ़ का खतरा स्थायी संकट है। खेतों में

दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में सूखाड़ स्थायी संकट है। खेतों में

कीचड़ पानी के अभाव में सूख जाते हैं। इसी का हल निकालने

के लिए नदी-लिंक योजना बनी, ताकि बाढ़ प्रभावित राज्यों

से अतिरिक्त पानी सूखा वाले राज्यों में पहुंचाया जा सके।

यह तभी संभव है, जब नदियों को जोड़ा जाए। जल प्रबंधन की

जरूरत के आधार पर सामूहिक बनाने के लिए जब स्टोरेज,

नहर समेत वर्षा जल-संचय का काम शुरू हुआ।

लेकिन कितनी भी नदी-लिंक परियोजना बनी, सब की

सब विवादों से घिरी है।

केन-बेतवा लिंक रिकॉर्डर अजनबी के रूप में नदी जोड़ो की आधारशिला है, इसे पास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि में मिली जा रही थी। लेकिन विशेषज्ञों की राय में अमल में लाने से पहले अभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड को पानी मिलेगा या नहीं, यह तो अभी भविष्य में ही पता चलेगा लेकिन और केन तट पर छतरपुर जिले के 10 गांवों के जलमग्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। केन-बेतवा लिंक में मध्यप्रदेश डैम पर ऊपर लोअर हैं। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं।

नदियों को जोड़ने में अभी तक आशानुकूल सफलता नहीं मिलने का कारण राज्य सरकारों का आपस में नदियों का राजनीतिक नहीं जुड़ना है। इसकी वजह क्षेत्रीय और वालों के लिए दुर्भाग्य लिए में संजोए राज्यों का पानी के लेन-देन रहना है। ऐसा नहीं है कि नदी-लिंक में पानी के लेन-देन अलग-अलग दलों की सरकारें लिंक जरूर-बदलो के लिए अलग-अलग दलों की सरकारें लिंक प्रस्ताव आगे बढ़ाने की बात करती है। दरअसल की अपने इलाके के नागे स्वार्थ बात करते हैं। जब लिंक अपने इलाके को क्षेत्रीय पक्ष हावी रहता है। जब लिंक सरकारें एक ही अपना क्षेत्रीय पक्ष नहीं छोड़ेंगे। लिंक जोड़ने वाली बातें नहीं जुड़ेंगी, तो नदियां कैसे जुड़ेंगी। लिंक जोड़नेवाली बातें नहीं जुड़ेंगी तो नदियों को तोड़ रही हैं। (पातालगंगा-पेन्नार लिंक, कावेरी जल विवाद, नर्मदा जल विवाद तब नदी-लिंक योजना के इतिहास का बहुविवादित अध्याय बन चुका है। राज्यों में सरकारें बदलीं, केंद्र में सरकारें बदलीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते निर्देश देते-देते थक चुकी। न नदियां जुड़ीं, न लोग जुड़े।

→ ०

Date: ~~08/03/2024~~

① nbt.regnews @ timesgroup.com

rahul.ayodhya @ gmail.com

② chandansharma @ gmail.com

③ editorial @ sanmarg.in

④ dainikpurvoday @ gmail.com

⑤ [redacted] 6393076351 (whatsapp)
Purvanchalprahari

⑥ haribhoomi @ gmail.com

⑦ vinay.bhushan @ farrukhabadkhabar.in